

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर में वे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे व करणी माता की पूजा-अर्चना करेंगे

बीकानेर/जयपुर, 16 मई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे और जिले के देशनोक में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के वीर जवानों के साहस और पराक्रम को नमन करेंगे।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर दोपहर 1:10 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 1.15 बजे प्रस्थान कर, वे दोपहर 1:35 बजे रिंदि सिंढि भवन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:35 बजे यहां से प्रस्थान कर सायं 4 बजे वे पलाना गांव में एक

- मुख्यमंत्री जयपुर से बीकानेर नाल एयरपोर्ट पर दोपहर 1:10 बजे पहुंचेंगे तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सायं 7:20 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिये प्रस्थान करेंगे।**

स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद सायं 5:10 बजे देशनोक के करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद, देशनोक में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। यहां से सायं

6:30 बजे प्रस्थान कर सायं 7:15 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा सायं 7:20 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलुगाम में भारतीय नागरिकों पर आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले की जवाबी कार्रवाई “आपरेशन सिंदूर” में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया था। इस ऑपरेशन की गौरवमयी सफलता पर देशभर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बीकानेर के देशनोक में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान, मुख्यमंत्री देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे।

जगदुरू रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ सम्मान

नयी दिल्ली, 16 मई । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां एक समारोह में संस्कृत के विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने इस अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार को भी बधाई दी जो अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने गुलजार जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

मुर्मु ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है।

गुजरात समाचार, मालिक, बाहुबलि शाह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने भारी ‘‘साज़िश’’ बताया

- पत्रकारिता से जुड़े लगभग सभी संगठन व संस्थाओं, जैसे प्रेंस क्लब ऑफ इण्डिया, वुमन्स प्रेंस कॉर्प्स प्रेंस एसोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड, ईवेली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरला यूनियन ऑफ वॉर्किंग जर्नलिस्ट्स आदि ने गुजरात के सबसे बड़े व प्रमुख अखबार के मालिक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को ‘‘जनता की आवाज़’’ दबाने की साज़िश बताया।**

अखबार गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया है, जो बेहद शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। यह गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है, क्योंकि इस अखबार ने पिछले 25 वर्षों से मोदी-शाह की नीतियों की आलोचना कर दिखाई है।

शाह बंधुओं के घर और दफतरो पर ईडी और इनकम टैक्स छापों के बाद गिरफ्तारी हुई है।

प्रख्यत गुजराती पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्य शीला भट्ट ने एक्स पर लिखा, ‘‘सरकार द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर कदम है। गिरफ्तारी के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली शाह को जांच के लिए सरकारी वी.एस. अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, और फिर उन्हें ज़ायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, श्रेयांश शाह ज़ायडस अस्पताल में बाहुबली शाह की देखभाल कर रहे हैं। श्रेयांश शाह ने मीडिया को बताया कि वे ‘‘लड़ाई जारी रखेंगे।’’ दोनों भाईयों के पास अखबार के अलावा अन्य व्यवसाय भी हैं। श्रेयांश शाह को गुजरात की राजनीति का सबसे तेज दिमाग माना जाता है।’’

शशि थरुर भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के आधिकारिक विचार नहीं हैं।
थरुर को प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाये जाने की केन्द्र सरकार की पेशकश को नुकसान रहित सामान्य प्रक्रिया माना जा रहा है, क्योंकि वे विदेशी मामलों से सम्बंधित संसद की स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, भले ही कांग्रेस के कुछ ग्रुप इसे, इस पूरे घटनाक्रम में एक राजनैतिक संदेश के रूप में देख रहे हों। थरुर के लिये राहत की बात यह है कि स्वयं कांग्रेस ने भी इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है, जो यूरोप के विभिन्न देशों सहित, अन्य कई देशों में जायेगा तथा वहाँ पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने आज इस बात की पुष्टि कर दी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू ने इस सम्बंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे से बात की थी तथा ‘‘कांग्रेस निश्चित रूप से

इस (प्रतिनिधिमंडल) का हिस्सा रहेगी।’’ थरुर ने स्वयं भी इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाया है। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सरकार से कह दिया था कि वह इस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी से बात करे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिन्दूर और उसके बाद की स्थिति पर उनके विचार उनके ‘‘निजी विचार’’ थे।

कई प्रतिनिधिमंडल, जिनमें से प्रत्येक में 5-6 सांसद होंगे, विभिन्न देशों में जाकर पाक-समर्थित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। आशा की जा रही है कि ये प्रतिनिधिमंडल 22 मई को भारत से रवाना होंगे तथा जून के प्रथम सप्ताह में वापस आ जायेंगे। इनमें शामिल सम्भावित सांसद हैं- समिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, समित्त पात्रा, सुप्रिया सुले तथा डी. पुरन्देश्वरी।

एकल पट्टा प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
और सुनने का निवेदन किया। इस दौरान, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले को सुनवाई जुलाई माह में रखी है। गौरतलब है कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। जमीन तय सीमा से अधिक होने के कारण जेडीए ने साल 2005 में प्रकरण राज्य सरकार को भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने पट्टा देने से इनकार कर दिया। वहीं, साल 2009 में आवेदन होने पर जेडीए ने मामले को पुनः राज्य

सरकार के समक्ष भेजा। राज्य सरकार ने साल 2011 में पट्टा जारी कर दिया, जिसे साल 2013 में निरस्त कर दिया गया। वहीं, रामशरण सिंह ने साल 2014 में एसीबी में शिकायत दी थी। मामले में हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई रद्द करते हुए, तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के इन आदेशों को रद्द कर पुनः छह माह में सुनवाई पूरी करने को कहा था।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पुणे गए, वहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी. सतीश से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी माता स्नेहप्रभा वेलंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका हाल ही में निधन हो गया था।

अवमानना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उसने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 जनवरी, 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह प्रदेश या अन्य राज्य से याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स कराए और पद खाली होने पर उसे नियुक्ति दे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2023 को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को न तो ब्रिज कोर्स कराया और न ही उसे नियुक्ति दी। ऐसे में दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों को दंडित कर अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है।

तीन माह में न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाए

- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को दिए निर्देश में भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम बनाने की हिदायत दी।**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट्स व राज्य सरकारें इन नियमों में अपनी जरूरत के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।**

नयी दिल्ली, 16 मई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवा को देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे न्यायालय प्रबंधकों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंध में तीन महीने के भीतर नियम बनाएं या उनमें संशोधन करें और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जमा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

पीठ ने सचिन कुमार गुप्ता और एन.स, कोर्ट मैनेजर वेलफेयर एसोसिएशन और एक रिट याचिका पर अपने फैसले में यह भी कहा कि उन्हें सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये प्रवासी नेता बलूचिस्तान के लक्ष्य की दिशा में सिफारिश की थी और इस अदालत ने वर्तमान कार्यवाही में दो अप्रस्त 2018 के फैसले में विशेष रूप से न्यायालय प्रबंधकों की सेवा शर्तों, कर्तव्यों आदि को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था,

पहले कहा था कि प्रत्येक न्यायिक जिले में न्यायालय प्रशासन के निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से योग्य न्यायालय प्रबंधकों, जिसमें एमबीए डिग्री वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि न्यायालय प्रबंधन की दक्षता बढ़ने और प्रशासनिक कार्यों में जिला न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा न्यायालय प्रबंधकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव किया गया था, ताकि न्यायाधीश अपना समय न्यायनिर्णय होनी चाहिए, इसलिए यह भी आवश्यक है कि न्याय प्रशासन की दक्षता बढ़ने के लिए न्यायालयों को न्यायालय प्रबंधकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रणाली भी पूरे देश में काफी हद तक एक समान होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इससे

बलूच नेताओं ने हिन्दुस्तान में ‘‘गवरमेंट इन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बलूच, तारा चंद और अन्य बलूच नेता भारत से, एक निर्वासित सरकार स्थापित करने में सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए औपचारिक कार्य आरंभ किया जा सके। बलूचिस्तान का प्रवासी समुदाय अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट और यूरोप में फैला हुआ है, जो स्वतंत्र बलूचिस्तान के लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये प्रवासी नेता बलूचिस्तान के भीतर चल रहे आंदोलन से भी तालमेल बनाए हुए हैं। इन प्रवासी नेताओं का कहना है कि ‘‘क्रूर’’ पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में दमन और नियंत्रण की चरम सीमाएं पार कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के प्रमुख नेताओं और युवा स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर रही है और कड़्यों को मारा जा रहा है। तथापि, बलूच नेताओं को पूरा भरोसा है कि जल्दी ही

रज्जाक बलूच के अनुसार, बलूचिस्तान की क्वेटा में कैन्ट्रूमेंट के अलावा पाकिस्तानी सेना की कोई चहल कदमी नहीं है, बलूचिस्तान में, और धीरे-धीरे बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम जमीन पर काफी फैल गया है तथा स्वतंत्रता संग्राम को सफलता शीघ्र ही जरूर मिलेगी।
आजादी का यह आंदोलन सफल होगा और पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया जाएगा।
बलूच नेता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए एक संगठित निर्वासित सरकार के गठन की योजना बना रहे हैं। रज्जाक बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान भू-राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी स्वतंत्रता पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता ला सकती है।
महरंग बलूच और अन्य कई नेता बलूचिस्तान में जमीन पर काम कर रहे हैं। महरंग फिलहाल जेल में हैं और बलूच नेता उन्हें रिहा करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रज्जाक बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान में पंजाबी शासक असुरक्षित महसूस करते हैं और वे केवल क्वेटा की छावनी तक सीमित हैं। रज्जाक बलूच ने यह भी दावा किया कि बलूचिस्तान का 70-80 प्रतिशत हिस्सा पहले ही पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त हो चुका है और अब केवल राजधानी क्वेटा ही पाकिस्तान के नियंत्रण में है। बलूच नेता बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना शाम पांच बजे के बाद

वर्किंग न्यूज़ कैमरा पर्सन एसोसिएशन ने कहा कि यह कार्रवाई भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक गंभीर हमला है।

प्रेंस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया कि गुजरात समाचार, जो स्वतंत्र पत्रकारिता की लंबी विरासत रखने वाला एक सम्मानित प्रकाशन है, गुजरात और उसके बाहर के लोगों की एक सशक्त आवाज़ रहा है। बयान में कहा गया, ‘‘एक बार फिर, ईडी की गिरफ्तारी मीडिया हाउसों को दबाने और असहमति की आवाज़ों को खामोश करने के लिए राज्य तंत्र के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है।’’

बयान में यह भी कहा गया कि ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा बार-बार मीडिया की निशाना बनाना संविधान में निहित लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के कमजोर करता है और संस्थानों में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाता है।

गौतम लाहिड़ी ने आरोपों के बारे में पूरी पारदर्शिता की मांग करते हुए, अधिकारियों से प्रक्रिया की निष्पक्षता और कानून के शासन के पालन की अपील की।

बयान में कहा गया कि लोकतंत्र में सत्ता की जवाबदेही तय करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया को कुचलना तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना बंद होना चाहिए। अंत में, बयान में सरकार से प्रेंस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और बाहुबली शाह को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जब तक कि पारदर्शी तरीके से कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश न किया जाए।

सेना के रक्षा बजट में 5 0 हजार करोड़ रु. की वृद्धि

इसके बाद कुल रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगा

- समझा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार यह कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।**

नई दिल्ली, 16 मई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रक्षा बजट को 5 0 हजार करोड़ रुपये का बूस्ट देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप, भारत के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह वृद्धि संभवतः अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, यह वृद्धि कुल रक्षा आवंटन को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1

में 9.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बढ़े हुए बजट का उपयोग संभवतः अनुसंधान और विकास, तथा हथियार, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मानी जाएगी।

डिफेंस सेक्टर पर 2014 से ही नरेन्द्र मोदी सरकार का फोकस रहा है। भाजपा सरकार के पहले बजट 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। वर्तमान आवंटन सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और कुल बजट का 13 प्रतिशत है।

भारत की रक्षा तैयारी और (संभावित) बजट आवंटन में वृद्धि, पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हुई है। यह विशेष रूप से 22 अप्रैल के पहलुगाम आतंकी हमले और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर एतैयबा के आतंकी शिबिरों को निशाना बनाया गया था

राजनीतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
विलय की वार्ता गोपनीय रूप से चल रही है। नतीजे अनिश्चित हैं। जहाँ राजनैतिक जरूरत दोनों गुटों को पास ला रही है, वहीं अहं का टकराव व कई ऐसी शिकायतें हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ है और ये बड़ी बाधा पैदा कर रही हैं।अभी महाराष्ट्र का राजनैतिक परिदृश्य बेहद नाजुक है। दखना यह है कि क्या पुराने घावों और वैचारिक मतभेदों पर व्यवसायिक हितों और पारिवारिक रिश्तों को तबज्जो मिलेगी।

छावनी से बाहर नहीं निकल सकती।
बलूच नेताओं का कहना है कि उनका प्रबंध अपनी मातृभूमि पर अधिकार संचार करने का है। रज्जाक बलूच और अन्य बलूच नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूच युवाओं का नरसंहार कर रही है। उन्होंने बताया कि बलूच नेता अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी एक सशक्त अभियान चला रहे हैं। बलूच नेता यह भी कह रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब के पंजाबी लोगों का बलूचों या अरब देशों से कोई डीएनए या सांस्कृतिक संबंध नहीं है। पंजाबी और मिडिल ईस्ट लोगों में कोई कनेक्शन नहीं है। उनको विश्वास है कि वे अपने आत्म-निर्णय के अधिकार को अवश्य हासिल करेंगे।
उनका यह भी कहना है कि सिंध, पख्तिस्तान और बलूचिस्तान को आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता की अनुमति दी जानी चाहिए।

^[1] राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन. आई. नं.3641/57, ई-मेल-rastrdutr@gmail.com
कोटा कार्यालय:-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा
फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033
बीकानेर कार्यालय:-कुंभाधना हाउस, हनुमान हट्या, बीकानेर
फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371
उदयपुर कार्यालय:-आयुध, मेन रोड आयुध, उदयपुर
फोन:2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146
अजमेर कार्यालय:-जयपुर घाटी, जयपुर रोड,अजमेरा
फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665
जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर
फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424
हिरण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिरण्डीनसिटी
फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600
चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908